

स्वास्थ्य व्यय पर NHA रिपोर्ट

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, सकल घरेलू उत्पाद

मेन्स के लयः

स्वास्थ्य व्यय पर NHA रिपोर्ट के प्रमुख बढऱः

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) ने बताया कऱःसरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धऱःकी है, जसऱःसे आउट-ऑफ पॉकेट एक्सपेंडचऱःर (OOPE) वर्ष 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 64.2% था ।

- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार की गई थी, जसऱःसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) तकनीकी सचऱःवालय के रूप में नामऱःतऱः कऱःया गया था ।
- वऱःशऱःव स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य खऱःतों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली 2011 के आधार पर एक लेखा ढाँचे का उपयोग कर NHA अनुमान तैयार कऱःये जाते हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्रः

- यह 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मऱःशऱःन (NRHM) के तहत तकनीकी सहायता के लऱःये एक शीर्ष नकऱःया के रूप में कारऱःय करने हेतु स्थापऱःतऱः कऱःया गया था ।
- इसका अधऱःदेशऱः स्वास्थ्य और परऱःवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लऱःये राज्यों को तकनीकी सहायता के प्रावधान करने और क्ऱःषमता नऱःरमाण हेतु नीतऱःएवं रणनीतऱः बनाने में सहायता करना है ।

प्रमुख बढऱः

- कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी हऱःसऱःसेदऱःरी में वृद्धऱःः
 - 2017-18 के लऱःये देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हऱःसऱःसे में वृद्धऱः हुई थी ।
 - यह वर्ष 2013-14 के 1.15% से बढऱःकर वर्ष 2017-18 में 1.35% हो गया है ।
- प्रतऱःवऱःयकतऱः बढऱःा हुआ सरकारी खर्चः
 - वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के बीच प्रतऱःवऱःयकतऱःके हऱःसऱःब से सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपए से बढऱःकर 1,753 रुपए हो गया है ।
- प्राथमऱःके स्वास्थ्य देखभाल का हऱःसऱःसाः
 - वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमऱःके स्वास्थ्य सेवा का हऱःसऱःसा 2013-14 के 51.1% से बढऱःकर 2017-18 में 54.7% हो गया है ।
 - प्राथमऱःके और माध्यमऱःके देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के 80% से अधऱःके के लऱःये ज़मऱःमेदार है ।
- स्वास्थ्य पर सामाजऱःके सुरक्षा व्ययः
 - स्वास्थ्य पर सामाजऱःके सुरक्षा व्यय का हऱःसऱःसा, जसऱःमें सामाजऱःके स्वास्थ्य बीमा कारऱःयक्रम, सरकार द्वारा वतऱःतऱःपोषतऱः स्वास्थ्य बीमा योजनऱःएँ और सरकारी कऱःर्मचारऱःयों को की गई चकऱःतऱःसा प्रतऱःपूरतऱः शामिल है, में वृद्धऱः हुई है ।
- जेब खर्च में कमीः
 - स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च में वृद्धऱःके कारण कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी खर्च का हऱःसऱःसा बढऱःकर 40.8 फीसदी हो गया और 2017-18 के लऱःये जेब खर्च में 48.8% की गरऱःवट आई ।
 - OOPE में गरऱःवट सरकारी स्वास्थ्य सुवधऱःओं के बढऱःते उपयोग और इन सुवधऱःओं एवं सेवाओं की लागत में कमी के कारण है ।

स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे:

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव:** देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का दायरा सीमित है।
 - जहाँ तक एक अच्छी तरह से काम करने वाले सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है तो वहाँ केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमिति चाइलडकेयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **आपूर्ति-पक्ष की कमियाँ:** बदतर स्वास्थ्य प्रबंधन कौशल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये उचित प्रशिक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की वांछित गुणवत्ता के वितरण को अवरुद्ध करती है।
 - वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिंस बलूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 100 में से लगभग एक बच्चे की मृत्यु दस्त या नमोनिया के कारण पाँच वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है।
 - स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच का प्रत्यक्ष संबंध डायरिया, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण पर व्यय लगातार कम हो रहा है (जीडीपी का लगभग 1.3%)। भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3% है।
 - यह आवंटन 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' (OECD) देशों के औसत (7.6%) और ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर किये जाने वाले औसत खर्च (3.6%) की तुलना में काफी कम है।
- **अतव्यापी क्षेत्राधिकार:** सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु उत्तरदायी कोई एक वशिष्ट प्राधिकरण नहीं है, जो कानूनी रूप से दिशा-निर्देश जारी करने एवं स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को लागू करने हेतु अधिकृत है।
- **उप-इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली:** इसके कारण उन गैर-संचारी रोगों से नपटना चुनौतीपूर्ण है जहाँ रोकथाम और रोग की आरंभिक पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है।
 - यह कोविड-19 महामारी जैसे नए और उभरते खतरों के लिये पूर्व-तैयारी और प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को सीमित करती है।
- **आवश्यकता से कम डॉक्टर:**
 - भारत में वर्तमान में WHO के 1:1000 के मानदंड के मुकाबले 1,445 की आबादी पर एक ही डॉक्टर मौजूद है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- [जननी शशि सुरक्षा कार्यक्रम \(JSSK\)](#)।
- [राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम \(RBSK\)](#)।
- [निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क नदान सेवा पहलों का कार्यान्वयन](#)।
- [प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम](#)।
- [आयुष्मान भारत](#)।
- [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(AB-PMJAY\)](#)

आगे की राह

- लागत को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु मेडिकल कॉलेजों में नविश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- अन्य नैदानिक प्रक्रियाओं और अस्पतालों में सार्वजनिक नजिी भागीदारी (PPP) पर जोर देना तथा लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति के लिये टीकाकरण अभियान में नजिी क्षेत्र की वशिषज्जता का लाभ उठाना।
- नई दवाओं के विकास में अधिक नविश का समर्थन करने और जीवन रक्षक व आवश्यक दवाओं पर 'वस्तु एवं सेवा कर' को कम करने के लिये अतिरिक्त कर कटौती द्वारा अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना।
- लोगों को प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को तैयार करने के लिये उनके प्रशिक्षण, पुनः कौशल और ज्ञान उन्नयन पर ध्यान देना आवश्यक है।

स्रोत: द हद्दि